Inclusion of Washermen in the List of SC/ST in Madhya Pradesh

398. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that washermen living in three districts of Madhya Pradesh i.e. 'Rai-Sen, Sihor, and Bhopal have been placed in the category of Scheduled Castes;

(b) whether it is also a fact that Washermen living in the rest of 42 districts of Madhya Pradesh have been deprived of being declared as scheduled Castes;

(c) whether the washermen living in other districts are also proposed to be declared as Scheduled Castes; if so, by when; and

(d) whether any representations have recently been received from any washermen associations and others to consider their case of being included in the Scheduled Castes list favourably; if so, what is Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI SUMATI ORAON): (a) and (b) Dhobi community have been included in the list of Scheduled Castes only in three districts of Madhya Pradesh i.e. Bhopal, Raisen and Sehore. In other parts of the State, they have not been included in the list of Scheduled Castes.

(c) and (d) Certain representations have been received regarding inclusion of Dhobi community in the list of Scheduled Castes in whole of Madhya Pradesh. All the representations will be considered before a comprehensive proposal for amending the lists is brought before Parliament.

खाद्यान्नों के उत्पादन पर सूखे का प्रभाव

399. **श्री सीर्जा इर्शाद बेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूखे के कारण कितनी कृषि भूमि प्रभावित हुई हैं;

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) किसानों को ऋण, बीज और भूमि सुधार के रूप में किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में सूखे के कारण 44.66 मिलियन हैक्टेयर सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ ।

(ख) देश के अधिकांश भागों में गम्भीर सूखा तथा पूर्वी राज्यों में बार-बार तथा लम्बी अवधि तक आई बाढ़ों के कारण खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा नहीं हैं । तथापि, रबी मौसम के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विस्तृत नीति कार्यान्वित की जा रही है ।

(ग) सूखा राहत कार्यों के अन्तर्गत राज्यों के लिए विभिन्न मदों हेतु व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर कर दी गई है। इसमें कृषि आदानों हेतु राज-सहायता, पशु संरक्षण तथा चारा आपूर्ति के लिए सहायता तथा अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने के लिए सहायता शामिल है ।

राजस्थान और गुजरात सरकारों से सूखा राहत के लिए अभ्यावेदन

400. **श्री सीर्जा इर्शाद बेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पन्न सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या योजनाएं